क्या केवल कागज़ पर दूर हुआ कुष्ठ रोग?

भारत डोगरा

कुष्ठ रोग या लेप्रसी के मामले में आज देश के सामने बहुत अजीब स्थिति है कि जहां एक ओर सरकारी कागज़ों में 'जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में' इसकी समाप्ति होने की औपचारिक घोषणा हुए सात वर्ष बीत गए हैं, वहीं वास्तव में काफी बड़ी संख्या में इसके नए मामले सामने आते जा रहे हैं।

इस विरोधाभास भरी स्थिति को समझने के लिए हमें वर्ष 2000 के आसपास की स्थिति को समझना होगा जब विश्व में सबसे अधिक कुष्ठ रोग के मामले भारत में ही दर्ज हो रहे थे और यहां कुष्ठ रोग की समाप्ति घोषित होने पर ही विश्व स्तर पर ऐसी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हो सकती थी। इस स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों और भारत सरकार दोनों की ओर से ऐसे निर्देश दिए गए कि कुष्ठ रोग के नए मामले तभी दर्ज किए जाएं जब कई नई शर्तें पूरी होती हों। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों में अब केवल उनकी गिनती की जाने लगी जिनके नाम एक विशेष तिथि को सरकारी मान्यता प्राप्त रजिस्टर में दर्ज थे।

इसके अतिरिक्त पूरी तरह मनमाने ढंग से एक नया मानदंड तैयार किया गया कि यदि कुष्ठ रोगियों की संख्या 1 मरीज़ प्रति 10000 आबादी के अनुपात से कम हो गई तो 'जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में' यह रोग समाप्त हुआ मान लिया जाएगा। इस मानदंड को तैयार करने का कोई आधार नहीं था। वर्ष 2005 के अंत में यह घोषित किया गया कि कुष्ठ रोग का अनुपात आबादी में 1 प्रति 10000 से कम हो गया है। इसका स्तर 0.95 बताया गया था। इस आधार पर 'जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में' कुष्ठ रोग की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

पर इसके बाद भी देश में कई स्थानों पर देखा गया कि कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक पाई जा रही है व नए रोगी भी काफी संख्या में सामने आ रहे हैं। मसलन, वर्ष 2000-01 में आगरा में हुए सर्वेक्षण में कुष्ठ रोग की उपस्थिति 34 प्रति 10000 आबादी दर्ज की गई। साथ ही नए केस पता लगने की दर 28 प्रति 10000 आबादी थी जो बहुत अधिक है।

कुष्ठ रोग नियंत्रण से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ता मनोज वर्मा कहते हैं, "क्या केवल सरकारी कागज़ में लिख देने भर से ही कोई स्वास्थ्य समस्या दूर हो जाती है? हम तो ग्रामीण अस्पतालों में निरंतर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मरीज़ इलाज के लिए आ रहे हैं व इनमें नए मरीज़ों की संख्या भी काफी अधिक होती है।"

हाल के वर्षों में एक समस्या यह भी देखी गई है कि कुष्ठ रोग के इलाज के लिए जो दवा दी गई है, उसका डोज़ आवश्यकता से काफी कम रहा है। इस कारण सरकार का खर्च चाहे कम हुआ हो, पर रोगियों के ठीक होने की संभावना कम हो गई है जो बेहद चिंताजनक है।

एक विशेषज्ञ पी. फीन्स्तरा ने लिखा है कि कुष्ठ रोग को समाप्त घोषित करने में राजनीति हावी हो गई है और इसे एक राजनीतिक लक्ष्य बना दिया है। बी. नाबस ने अपने अनुसंधान पत्र 'लेप्रसी इलाज - विज्ञान या राजनीति' में लिखा है कि जल्दबाज़ी में समाप्त घोषित करने से कुष्ठ रोग के वास्तविक नियंत्रण व इलाज पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है।

सरकार को चाहिए कि कुष्ठ रोग की सही स्थिति सामने रखे तथा सभी रोगियों के लिए इलाज के प्रयास व कुष्ठ रोग के नियंत्रण के समुचित उपायों में कोई कमी न आने दे। ***(स्रोत फीचर्स)***